

सोलर सिटी की राह पर काशी, लक्ष्य से अधिक आवेदन



जागरण संवाददाता, वाराणसी : पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तो पूरे देश में लागू है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जिले में 75,000 घरों पर सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित था। इसके सापेक्ष 78,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण करा लिया है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बीते वर्ष फरवरी में लागू हुई। इसके बाद जनपद में बिजली सब स्टेशन के हिसाब से 75,000 घरों पर तीन वर्ष में सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए जनपद में लक्ष्य का निर्धारण कर, उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने, सोलर

- जनपद में 9,000 से अधिक घरों की छतों पर सोलर संयंत्र स्थापित
- प्रशासन के प्रयास से प्रदेश में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा जिला

वाराणसी सोलर सिटी बनने की दिशा में अग्रसर है। हम पूरी कार्य योजना बनाकर आम आदमी के साथ कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, छोटे-बड़े संस्थान को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हम इसी माह 10,000 सोलर संयंत्र लगा लेंगे।
- एसके गुप्ता, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी।

संयंत्र लगाने वाले वेंडर और बैंकर को साथ लेकर आगे कदम बढ़ाया गया। सभी सरकारी विभागों को लक्ष्य देकर सहयोग लिया गया। वाराणसी माडल की सफलता को इससे समझा जा सकता है कि 9,000 से अधिक घरों पर सोलर संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। इसके अलावा 78,000 लोग पंजीकरण कराकर संयंत्र लगवाने की कतार में हैं। अब तो बिना ब्याज के ऋण, सभी सरकारी कर्मचारियों,

बैंक व ईपीएफ कर्मचारियों को अपने घरों पर लगाने के आदेश, स्कूल, कालेज, सरकारी भवन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 25 किलोवाट से अधिक खपत वाले कार्यालयों पर रिन्यूएबल इनर्जी सर्विस कंपनी (रेस्को) मोड में बिना किसी खर्च के लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

25 वर्ष तक बिजली मुफ्त : एक किलोवाट के लिए 10 वर्गमीटर छायामुक्त स्थान की जरूरत होती है।

उपभोक्ता के घर में जितने किलोवाट का विद्युत कनेक्शन है उतने का ही सोलर संयंत्र लगाने पर सब्सिडी दी जाती है। बिजली लोड बढ़ाने की सुविधा भी बिजली विभाग प्रदान कर रहा है। तीन किलोवाट के संयंत्र से प्रतिमाह करीब 3,000 रुपये की बिजली का उत्पादन होता है। उपभोक्ता एक बार सोलर संयंत्र लगवाकर 25 वर्ष तक लाभ प्राप्त कर सकता है।

75,000	के सापेक्ष पीएम सूर्य घर बिजली योजना के लिए 78 हजार ने कराया पंजीकरण
तीन किलोवाट के संयंत्र पर खर्च व अनुदान	
1,80,000 रुपये पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत	
30,000 रुपये राज्य सरकार की सब्सिडी	
78,000 रुपये केंद्र सरकार की सब्सिडी	
1,08,000 रुपये कुल सब्सिडी	
72,000 रुपये उपभोक्ता का अनुमानित खर्च	